RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 29 फरवरी 2024 वर्ष 05 अंक 308 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई नगर निगम कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का होगा तबादला

चुनाव आयोग ने दिया ट्रांसफर का आदेश

मुंबई : मुंबई नगर निगम कमिश्नर इकबाल सिंह चहल का ट्रांसफर किया जाएगा. चुनाव आयोग ने राज्य सरकार की ट्रांसफर रोकने की मांग को खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग ने बृहन्मुंबई नगर निगम आयुक्त इकबाल सिंह चहल के स्थानांतरण को रोकने के लिए नगर आयुक्त पर तीन साल का मानदंड लागू नहीं करने की राज्य सरकार की मांग को खारिज कर दिया है. इसलिए अब चहल सहित अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिड़े और कुछ अन्य अधिकारियों का तबादला किया जाना है.

नगर निगम आयुक्त इकबालसिंह चहल का स्थानांतरण अपरिहार्य

पिछले हफ्ते, चुनाव आयोग ने नगर निगम आयुक्तों, अतिरिक्त आयुक्तों के तबादले का आदेश दिया जो तीन साल या उससे अधिक समय से पद पर हैं। इस आदेश के चलते मुंबई चहल समेत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर करना पड़ेगा. इस बीच, राज्य सरकार ने अनुरोध किया था कि नगर निगम आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त को स्थानांतरण आदेश से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे सीधे चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं थे. राज्य सरकार ने इस संबंध में सोमवार को चुनाव आयोग को पत्र भेजा था. हालांकि, आयोग ने मंगलवार को सरकार के इस अनुरोध को खारिज कर दिया है. इसलिए अब नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त का तबादला होना तय है.

चुनाव आयोग का स्पष्ट आदेश

चुनाव आयोग ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जो नगर निगम आयुक्त या अपर आयुक्त तीन साल या उससे अधिक समय से पद पर हैं, उन्हें तबादला करना होगा. इसके चलते राज्य सरकार को चहल के साथ-साथ अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे और कुछ अन्य नगर पालिकाओं में अतिरिक्त आयुक्तों का स्थानांतरण करना पड़ेगा.

फडणवीस को धमकी... दो पर एफआईआर दर्ज

गोली मारने और जिंदा गाड़ने की बात कही

मुंबई : सांताक्रूज पुलिस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री-गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान आरोपी पर फडणवीस को धमकी देने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया के फेसबुक पर धमकी भरा वीडियो अपलोड करने के मामले में पुलिस ने इस शख्स के अलावा एक दूसरे के खिलाफ भी अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि, सामाजिक कार्यकर्ता और शिवसेना से जुड़े अक्षय पनवेलकर (32) की शिकायत के आधार पर सांताक्रूज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वीडियो में आरोपी ने कथित तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता को गोली मारने की बात कही और यह भी कहा कि वह उन्हें छह फीट नीचे गाड़ देगा। शिकायत के अनुसार, वीडियो फेसबुक पर योगेश सावंत नामक व्यक्ति द्वारा अपलोड किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि, सावंत पर उस व्यक्ति के साथ मामला दर्ज किया गया है। जिसने कथित तौर पर साक्षात्कार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को जान से मारने की धमकी दी थी।

मुख्यमंत्री शिंदे के 'जाली' हस्ताक्षर और मोहर वाला मिला ज्ञापन..

मुख्यमंत्री ने दिए कर्मचारियों को यह आदेश...

मुंबई महाराष्ट्र CMO को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के 'जाली'हस्ताक्षर और मोहर वाला ज्ञापन मिला है, जिसके बाद शिंदे के कार्यालय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के एक बयान में बुधवार को कहा गया कि शिकायत मरीन लाइन्स पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। दरअसल, सीएमओ आगे की कार्रवाई के लिए टिप्पणियों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन और पत्र प्राप्त करता है। पहले इन दस्तावेजों को डाक अनुभाग और ई-ऑफिस प्रणाली के साथ पंजीकृत किया जाता है और फिर संबंधित विभागों को भेज दिया जाता है।

कर्मचारियों को अधिक सतर्क रहने का आदेश

सीएमओ ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय को मुख्यमंत्री के फर्जी हस्ताक्षर और मोहर वाले 10 से 12 ज्ञापन प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और सीएमओ को पुलिस में शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने कार्यालय कर्मचारियों को अधिक सतर्क रहने का आदेश दिया है।

वर्षा गायकवाड़ को अमित साटम ने विधानसभा में किया सवाल

राहुल गांधी कहां-कहां तमाशा करते हैं, मैं आपकों बता दूं?

मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडल के अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के तीसरे दिन विधायक एवं मुंबई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड व प्रणीति शिंदे की सत्तारूढ़ बीजेपी विधायकों के साथ तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान भाजपा विधायक अमित साटम ने वर्षा को चेतावनी भरे लहजे में पूछ लिया कि उनके नेता राहुल गांधी कहां-कहां तमाशा करते हैं, मैं आपकों बता दूं?

बता दें कि विपक्षी विधायकों ने बुधवार को विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर गठबंधन सरकार से 293 के मुताबिक राज्य के विभिन्न मुद्दों पर जवाब देने को कहा था। इस प्रस्ताव पर बोलते हुए विधायक और आशीष शेलार ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्ववाली पूर्ववर्ती महाविकास आघाडी सरकार ने किसानों का पूरा कर्ज माफ करके कर्ज मुक्त करने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? पहले विपक्ष को इसका जवाब देना चाहिए बाद में हमसे सवाल पूछना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के प्रस्ताव को उनकी नाकामी पर पर्दा डालने की कोशिश बताया और आलोचना करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव चोर के शोर मचाने जैसी बात है। अपने संबोधन के दौरान आशीष शेलार ने पूर्ववर्ती महाविकास आघाडी सरकार की कमियां और बीजेपी, शिवसेना (शिंदे) और राकां (अजित) के गठबंधन वाली महायुति सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उनके बयान को वर्षा ने सदन में सियासी बयान करार देते हुए सवाल खड़े किए थे। इस पर पहले आशीष और वर्षा के बीच तीखी नोकझोंक हुई और बाद में अमित साटम सहित कुछ और विधायक वर्षा से भिड़ गए।

वर्षा ने ये कहा...

दरअसल, आशीष के बयान पर वर्षा ने कुछ सवाल उठाए, उन्होंने मुंबई के मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि क्या मुंबई मनपा स्वायत्त है, दो पालकमंत्री मंत्री अपना कार्यालय खोलकर बैठे हैं। उन्होंने मुंबई का बजट तैयार करने वाले मनपा आयुक्त के तबादला की मांग की और कहा कि सरकारी पैसा पार्टी फंड के रूप में खर्च किया जा रहा है। डीप क्लीनिंग के कारण स्वच्छता अभियान के कर्मचारियों में बेरोजगारी में बढ़ रहे हैं। बचत समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके बाद मनपा में टेंडर को लेकर विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला। गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि आयुक्त ने अपने करीबियों के लिए नया टेंडर जारी किया। सरकार की भूमिका यह है कि वह अपने दोस्त को टेंडर कैसे दिलाए?

विदेशी मुद्रा बदलने के बहाने शख्स से 60 हजार रुपये की ठगी, 7 लोग गिरफ्तार

ठाणे: नवी मुंबई पुलिस ने भारतीय रुपये के बदले विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने के बहाने 37 वर्षीय एक व्यक्ति से 60 हजार रुपये की ठगी के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. अधिकारी के मुताबिक, घटना 23 फरवरी को महाराष्ट्र के नवी मुंबई के वाशी इलाके में हुई. सहायक पुलिस निरीक्षक पवन नंद्रे ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित को वाशी में एक मकान के पास बुलाया और उसे भारतीय रुपये के बदले अमेरिकी डॉलर देने की पेशकश की. पीड़ित, मुंबई के कुर्ला में मोबाइल ठीक करने की दुकान चलाता है. अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने आरोपियों को 60 हजार रुपये दिये लेकिन उन्होंने उसे विदेशी मुद्रा नहीं दी.

संपादकीय / लेख

शिमला के कफन ओढ़े मॉल रोड

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

शिमला के मॉल रोड पर कफन बिकने लगे, हमारी आंखों के सामने कत्ल दिखने लगे। जिस मॉल रोड पर हिमाचल की कानून व्यवस्था नाड़ा करती है। जहां भीड़ में भी शिष्टाचार की संगत चलती है। जहां पुलिस चौकसी के इंतजाम गारंटी देते हैं कि हिमाचल शांत है, वहां पुलिस रिपोर्टिंग रूम में कफन ओढ़े एक युवा अपने ही कत्ल की शिकायत कर गया। यह इश्य वीभत्स है और हमारी व्यवस्था के सामने लाश बनकर कई प्रश्न उठा देता है। बेशक कत्ल की वारदात एक रेस्तरां के भीतर होती है, लेकिन गुनाह की परतें मॉल रोड से होकर गुजरीं और एक निर्मम हत्या की चीखों के बीच हमारे सन्नाटे नहीं टूटे। ये सन्नाटे तब भी नहीं टूटे जब एक पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए प्रहार को हमने सियासत के दर्पण में देखने की कोशिश की। इतना ही नहीं, वर्तमान विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा की हत्या की सुपारी एक खबर बनकर घूम रही है, लेकिन हम इस भ्रम में हैं कि इसके पीछे कुछ तो सीलबंद सियासत है। शिमला मॉल पर हत्या दरअसल मॉल रोड की हत्या सरीखी है, क्योंकि जहां कोई पंख नहीं मार सकता, वहां अब अपराध के वर्चस्व की खबर इसके कानों तक नहीं। हम अलग-अलग कारणों से पिछले दिनों की पुलिस को अदालत में खड़ा देखते हैं। कहीं किसी व्यापारी की शिकायत पर पुलिस प्रक्रिया को देखते हैं, तो पदों की खुशामद में वफादारी देखते हैं। कहीं तो लचर हैं हमारे हाथ, वरना चूड़ियां हमें क्यों मिलतीं। हम कानून व्यवस्था के मानदंड को इस खुशफहमी में नहीं देख सकते कि हिमाचल भोले-भाले लोगों का प्रदेश है। कानून के आईनों में धूल झोंकने के सबूत अब इसी की व्यवस्था में भी मौजूद हैं। आर्थिक गतिविधियों में इजाफा, नई आर्थिकी से निकलते रोजगार, अंतरराज्यीय अपराधों की जुगलबंदी, नशे के बढ़ते कारोबार और पर्यटन के मार्फत आता व्यापार साधारण नहीं है और न ही इसे सहजता से देखा जा सकता है।

जिस पुलिस की भर्ती में पेपर लीक जैसे अभिशाप हैं, वहां इसके दरमियान अपराध की गुंजाइश प्रमाणित नहीं तो फिर ऐसा क्यों है कि एक व्यापारी ने ही आरोपों से कई स्तंभ गिरा दिए। दूसरी ओर समाज की दृष्टि में आ रहे खोट ने भी जीवन को प्रतिस्पर्धा का खिलौना बना दिया। हम आंकड़ों में खुद और व्यवस्था पर मेहरबानी दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत के पंजों में खतरों का हिसाब बढ़ा है। ऐसे में कानून व्यवस्था जो कल तक अवैध खनन, नशे की तस्करी तथा शराब व वन माफिया की करतूतों में खुद को पहरेदार दिखाती थी, आज उसकी आंखों में कई तरह का दोष बढ़ा है। राजधानी शिमला के मुख्य स्थल और कानून व्यवस्था के प्रतीकों में से सर्वश्रेष्ठ संज्ञा माना गया मॉल रोड अभिशप्त हुआ, तो कहीं सारी चौकसी और पुलिस सतर्कता का हुजूम भी हार गया। ऐसे में सवाल अब असहज होकर व्यवस्था परिवर्तन के विषय में सरकार से पूछ रहे हैं। हिमाचल में सतर्कता के मायने सडक से शहर तक और गांव से राजधानी की गरिमा तक बदलाव चाहते हैं। ऐसे में जब शहरी व्यवस्था में नगर निगम के अवतार बनाए जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि मौजूदा डेढ़ करोड़ पर्यटकों की आमद को पांच करोड़ तक पहुंचाएंगे, तो इसकी शुमारी और व्यवसाय की खुमारी में, नई कानून व्यवस्था क्या होगी। आम तौर पर और शहरी व ग्रामीण पुलिस के आचरण में व्यवस्था का आचरण बदलने की जरूरत रही है, लेकिन शिमला में राजधानी जैसे फलक को भी हम मात्र पुलिस कप्तानी में देख रहे हैं, जबकि यहां व मंडी, धर्मशाला तथा सोलन जैसे शहरों में अब पुलिस आयुक्तालय स्थापित करने होंगे। बेशक बीबीएन के बाद नूरपुर में अलग से एसपी कार्यालय खोल दिए गए हैं, लेकिन पर्यटक मार्गों, व्यस्त सडकों, अंतरराज्यीय संपर्क मार्गों पर पेट्रोलिंग व्यवस्था सशक्त करनी होगी। अब हिमाचल में पर्यटन पुलिस की अवधारणा में हर पर्यटक और धार्मिक स्थल की निगरानी होनी चाहिए।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalrokthok
#faisalrokthok

मोडकसागर, तानसा, विहार, तुलसी, मध्य वैतरणा, भातसा, अपर वैतरणा हो रहीं खाली

मुंबई में 1 मार्च से पानी कटौती !

मुंबई: बीएमसी के जलापूर्ति विभाग ने तालाबों में घटते जल स्तर को देखते हुए मुंबई में 1 मार्च 2024 से 10 प्रतिशत पानी कटौती करने का प्रस्ताव कमिश्नर आई. एस. चहल के पास भेज दिया है। प्रशासन ने राज्य सरकार से अपर वैतरणा और भातसा तालाब के रिजर्व वायर से अतिरिक्त पानी देने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब बीएमसी को नहीं मिला है। इसलिए बीएमसी ने मुंबई में पानी कटौती के लिए फाइल को आगे बढ़ा दिया है।

... तो मुंबई में करनी पड़ेगी पानी कटौती

बीएमसी के अडिशनल कमिश्नर पी. वेलरासू ने कहा कि मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली सातों झीलों में पिछले तीन साल के औसत से सबसे कम पानी है। इसलिए हमने राज्य सरकार के रिजर्व वायर से मार्च से जून के बीच 4 महीनों के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त पानी देने की मांग की है। मार्च, अप्रैल, मई और जून के लिए अतिरिक्त पानी मिलता है, तो मुंबई में पानी कटौती नहीं करनी पड़ेगी। यदि पानी नहीं मिलता है तो फिर 1 मार्च से मुंबई में 10 प्रतिशत पानी कटौती शुरू करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है।

14,35,458 एमएलडी पानी का स्टॉक

बीएमसी जलापूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल मॉनसून के दौरान 29 सितंबर के बाद झील क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई। इसके कारण 1 अक्टूबर 2023 को मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में 14,35,458 एमएलडी यानी 99.18 प्रतिशत पानी का स्टॉक था, जबकि बीएमसी के नियम के अनुसार 1 अक्टूबर को सातों झीलों में 14,47,363 एमएलडी पानी का स्टॉक है, तो अगले मॉनसून तक पानी कटौती की नौबत नहीं आती है। बता दें कि बीएमसी मुंबई को मोडक सागर, तानसा, विहार, तुलसी, मध्य वैतरणा, भातसा, अपर वैतरणा झील से प्रतिदिन 3850 एमएलडी पानी की आपूर्ति करती है।

वर्ष शेष पानी (एमएलडी में) प्रतिशत

24 फरवरी 2024	6,57,546	45
24 फरवरी 2023	7,32,037	50.58
24 फरवरी 2022	7,72,479	53.37

एसआईटी जांच में मंत्रियों की भी जांच की जाए - जरांगे पाटील

मुंबई: मराठा आंदोलनकारी कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गए आरोपों का असर दूसरे दिन भी विधानमंडल के बजट सत्र में देखने को मिला। विधान परिषद और विधानसभा में जरांगे का मुद्दा उठाया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जरांगे पाटील के समूचे आंदोलन की एसआईटी से जांच कराने का निर्देश सरकार को दिया। वहीं, विधान परिषद में बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने आरोप लगाया कि शरद पवार, जालना विधायक राजेश टोपे और रोहित पवार सहित एनसीपी शरद पवार गुट के नेताओं ने जरांगे के साथ बैठक की और सुनिश्चित किया कि कार्यकर्ता राज्य में अशांति पैदा करें।

मंगलवार को बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे पाटील ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जो आरोप लगाए हैं, वे काफी गंभीर हैं। जरांगे महाराष्ट्र को जलाने की बात कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं न होने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसकी फैक्ट्री में बैठकें हुईं, जेसीबी किसकी फैक्ट्री से आई? उस फैक्ट्री में पत्थर कहां से आए? इन बातों की एसआईटी जांच होनी चाहिए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मनोज जारंगे पाटील के आंदोलन की जांच एसआईटी से कराने के आदेश दिए। एसआईटी जांच के निर्देश दिए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि एसआईटी जांच करेगी कि जरांगे किसकी 'स्क्रिप्ट' बोल रहे हैं। जरांगे ने मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, लेकिन पूरा मराठा समाज मेरा समर्थन करता है।

विधानसभा में मराठा आरक्षण आंदोलन की एसआईटी जांच कराए जाने की घोषणा के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटील ने एसआईटी जांच की घोषणा का स्वागत तो किया, साथ ही चुनौती दी कि एसआईटी जांच में मंत्रियों की भी जांच की जाए। जरांगे पाटील ने अपने गांव में कहा कि मुझे किसी जांच का या किसी भी बात का कोई डर नहीं है। मैं चाहता हूं कि जांच हो तो पूरी हो, अधूरी जांच नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पहले से अंदेशा था कि सरकार उन्हें फंसाने के लिए जरूर कोई दांव खेलेगी। मैंने परसों ही इस बारे में अपने समाज के लोगों को संकेत दिया था।

बीएमसी ने मलाड ईस्ट रोड चौड़ीकरण परियोजना के लिए 168 संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया

मुंबई: बीएमसी ने मलाड पूर्व में 500 मीटर की सड़क को चौड़ा करने के लिए 168 आवासीय और वाणिज्यिक संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया। 2.1 किलोमीटर लंबी सड़क कांदिवली पूर्व को गोरेगांव पूर्व में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ेगी। इस परियोजना का लक्ष्य पूर्व-पश्चिम कनेक्टिविटी के लिए गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) परियोजना को आगे बढ़ाना है।गोरेगांव पूर्व से लोखंडवाला, कांदिवली पूर्व तक 36 मीटर चौड़ी और 2.1 किमी लंबी सड़क को नागरिक निकाय द्वारा एक महत्वपूर्ण परियोजना घोषित किया गया है। तदनुसार, बीएमसी ने इस सड़क के 500 मीटर के चौड़ीकरण का कार्य किया है, जिसे जीएमएलआर जंक्शन रत्नागिरी होटल से मलाड पूर्व में मलाड जलाशय तक रिजर्वायर रोड के रूप में जाना जाता है।ह्न9 मीटर चौड़ी सड़क को 36 मीटर तक चौड़ा किया गया है।

मराठा समुदाय के लिए लागू हुआ 10 फीसदी आरक्षण, अधिसूचना जारी...

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया है। विधि व न्याय कानून विभाग के सचिव सतीश बाघोले ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इससे अब राज्य में मराठा समुदाय के लोग शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। सरकार ने आयोग के माध्यम से मराठा समुदाय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर सर्वेक्षण कराया था।

सर्वेक्षण में यह पाया गया कि मराठा समुदाय के 84 प्रतिश परिवार उन्नत श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए वे इंदिरा साहनी मामले के मुताबिक आरक्षण के पात्र हैं। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 20 फरवरी को हुए विधानमंडल के विशेष सत्र में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने वाले विधेयक को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई थी।

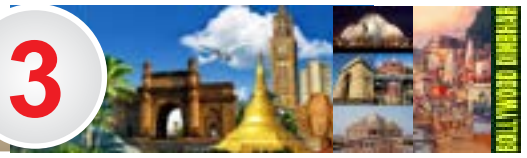

बसवराज पाटिल ने कांग्रेस छोड़ी,
लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में हुए शामिल

मुंबईः कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले बसवराज पाटिल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पाटिल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रकांत पाटिल की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। बसवराज पाटिल महाराष्ट्र के औसा निर्वाचन क्षेत्र से दो बार विधायक हैं। इससे पहले, आगामी लोकसभा चुनाव से पहले, सबसे पुरानी पार्टी को करारा झटका देते हुए, लगभग 55 पूर्व कांग्रेस विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के नक्शेकदम पर चलते हुए शनिवार को नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा, ''आज हमने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों से बात की, बातचीत अच्छी रही. हम सब मिलकर नांदेड़ में बीजेपी को जीत दिलाएंगे. इसमें कोई संदेह नहीं है.'' 55 पूर्व कांग्रेस विधायकों ने आज मुझसे मुलाकात की और भाजपा में शामिल होने की मंशा व्यक्त की। मैंने उनसे कहा कि उनका स्वागत है और उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए प्रवेश दिया।'' इससे पहले 21 फरवरी को, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण सहित भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों को सम्मानित किया और बधाई दी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण 13 फरवरी को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।

मीरा रोड पर रैली के बाद राजा सिंह के खिलाफ AIMIM महिला नेता ने खोला मोर्चा...

रिजवाना खान ने असदुद्दीन ओवैसी पर गलत टिप्पणी का लगाया आरोप, एफआईआर की मांग

मुंबईः मीरा रोड पर भड़काऊ भाषण के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एआईएमआईएम की नेता रिजवाना खान ने बीजेपी विधायक के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करनेाकी मांग की है। रिजवाना खान ने मीरा भायंदर जोन-1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ को लिखित शिकायत दी है। इसमें उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। रिजवाना खान महाराष्ट्र एआईएमआईएम की चर्चित और युवा नेता हैं। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने 25 फरवरी को मीरा रोड पर रैली निकाली थी। इसमें उनके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट की शर्तों को तोड़ने और भड़काऊ भाषण का आरोप लगा रहा है।

मीरा रोड पर बॉम्बे हाई कोर्ट की अनुमति पर बीजेपी विधायक टी राजा

सिंह ने 25 फरवरी को हिंदू रैली निकाली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश र टी राजा सिंह के भाषण की वीडियोग्राफी की गई है। ड्रोन से भी रैली पर नजर रखी गई थी। रिजवाना खाना का आरोप है कि राजा सिंह ने अपने भाषण में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गलत टिप्पणी की। इतना ही नहीं उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ दूसरी मस्जिदों को तोड़ने की बात कही। रिजवाना खान ने कहा कि उन्हें पुलिस की तरफ से मामला दर्ज करने का भरोसा डीसीपी ने दिया है। रिजवाना खान ने कहा कि उनकी पार्टी इस तहत के भाषण को बर्दाश्त नहीं करेगी। रिजवाना खान महिला एक सुरक्षा फाउंडेशन चलाती हैं। इसके साथ ही रिजवाना खान एमआईएमआईएम मुंबई महिला विंग की अध्यक्ष हैं।

मीरा रोड पर जारी है सियासी घमासान

मीरा रोड को लेकर बीजेपी और AIMIM के बीच काफी समय से बयानबाजी जारी है। मीरा रोड पर रैली में स्थानीय विधायक गीता जैन भी शामिल हुई थीं। उन्होंने भी रैली को संबोधित किया है। इस रैली में टी राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र के संघर्ष के लिए शपथ भी दिलवाई थी। टी राजा सिंह ने हुंकार भरी कि उन्हें आने वाले दिनों में अन्य मस्जिदों को खाली कराया जाएगा। उन्होंने कहा था कि हम अपनी कारसेवा जारी रखेंगे।

गोखले ब्रिज और सीडी बफीर्वाला पुल का नहीं हुआ अलाइनमेंट...

डिजाइन को लेकर मुंबई के लोगों ने उड़ाया BMC का मजाक

मुंबईः पश्चिम उपनगर में यातायात के लिए महत्वपूर्ण गोखले ब्रिज का एक हिस्सा सोमवार शाम को यातायात के लिए खोल दिया गया। मंगलवार को बड़ी संख्या में कार, ऑटो और दो पहिया वाहनों ने ब्रिज का इस्तेमाल किया। पहले दिन वाहन चालकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई थी। गोखले ब्रिज खोलने के बाद भी बीएमसी को सोशल मीडिया पर नागरिकों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंधेरी वेस्ट में गोखले ब्रिज सीडी बफीर्वाला ब्रिज को अलाइनमेंट नहीं किया गया है। गोखले ब्रिज की ऊंचाई बफीर्वाला ब्रिज से करीब डेढ़ मीटर ज्यादा है। इसीलिए ब्रिज के डिजायन को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक उड़ाया है। एक यूजर ने एक्स पर लिखा कि 'क्या मुंबईवासी लंबी छलांग लगा सकते हैं?' वहीं दूसरे ने लिखा है कि 'गोखले पुल पर गड़बड़ी करने के बाद सिविल इंजिनियर ने अपने बॉस को पकड़ लिया।' जबकि एक अन्य यूजर ने लिखा है कि इसके लिए तालियां बजाई जानी चाहिए।

बीएमसी में पूर्व नेता विपक्ष रहे रवि राजा ने कहा कि यह बीएमसी प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है। जब गोखले ब्रिज की ऊंचाई बढ़ गई तो बफीर्वाला ब्रिज के साथ उसे मैच क्यों नहीं किया गया। रवि राजा

ने कहा कि मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखूंगा कि इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं, बीएमसी कमिश्नर ने इसमें किसी तरह की गड़बड़ी न होने की बात कही है। उन्होंने ब्रिज निर्माण में रेलवे की पॉलिसी के चलते ऐसा होने की बात कही है।

नई पॉलिसी से हुई दिक्कत

गोखले और बफीर्वाला ब्रिज के बीच गैप के मुद्दे पर बीएमसी कमिश्नर आई.एस. चहल ने ब्रिज डिपार्टमेंट के इंजिनियर्स का बचाव किया। उन्होंने कहा कि ब्रिज निर्माण के दौरान रेलवे की नई पॉलिसी के कारण ब्रिज की ऊंचाई 1.5 मीटर बढ़ानी पड़ी। जबकि गोखले ब्रिज के निर्माण के दौरान बफीर्वाला ब्रिज के साथ डिजाइन तैयार किया गया था। लेकिन अचानक गोखले ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने के कारण बफीर्वाला फ्लाईओवर पुराने गोखले पुल के नीचे चला गया। हालांकि हमारे पास इस समस्या के समाधान के लिए वीजेटीआई और आईआईटी जैसे संस्थान हैं। यदि आवश्यक हो तो हम बफीर्वाला फ्लाईओवर से गोखले तक यातायात के सुचारू करने की अनुमति देने के लिए एक रैंप लगाने पर भी विचार कर सकते हैं।

बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों के नामों का किया ऐलान

पंकजा मुंडे समेत इन नेताओं को मिली महाराष्ट्र की जिम्मेदारी

मुंबईः बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है. चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी कर दी है, ताकि वे लोग चुनावी तैयारियों की समीक्षा कर सकें और जीत का प्लान बना सकें. बीजेपी ने महाराष्ट्र की 23 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी है. इसमें विभिन्न विधायक, मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. बीजेपी ने मिशन 400 का ऐलान किया है, इसे ध्यान में रखते हुए ही लिस्ट जारी कर दी गई है. पर्यवेक्षकों की लिस्ट के मुताबिक, उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र की प्रभारी पंकजा मुंडे को बनाया गया है. ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन

उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी हैं. वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार बीड लोकसभा की समीक्षा करेंगे. चुनाव निरीक्षक स्थानीय लोकसभा क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे. स्थानीय विधायकों, सांसदों और प्रमुख पदाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की जाएगी.

महाराष्ट्र में क्या है सियासी गणित और कैसा था पिछला रिजल्ट?

देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी के अलावा शिवसेना (उद्धव गुट), शिवसेना (शिंदे गुट), कांग्रेस, एनसीपी जैसी पार्टियां हैं. महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है. बीजेपी के मिशन 400 के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे अहम राज्यों में से एक है. पिछली बार हुए चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था. बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 23 पर उसे जीत मिली, जबकि शिवसेना 18 सीटें जीतने में कामयाब रही थी. एनसीपी उस वक्त विभाजित नहीं थी और उसने चार सीटों पर जीत हासिल की थी. इसके अलावा कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को भी एक सीट पर जीत मिली थी. हालांकि, इस बार चुनावी समीकरण बदल चुके हैं. इसकी वजह ये है कि एनसीपी भी अजित पवार और शरद पवार गुट में बंट चुकी है. जबकि शिवसेना में भी विभाजन हुआ है. इस बार एनसीपी (शरद गुट), शिवसेना (उद्धव गुट) और कांग्रेस साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद गुट) को मिलकर बना महाविकास आघाडी (एमवीए)ने कहा कि वे महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से अधिकतर के बंटवारे पर समझौते पर पहुंच गए हैं और अंतिम बैठक बुधवार को होगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने बताया कि अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों पर हमारी सहमति बन गई है.

शिवसेना के अकाउंट से 50 करोड़ किसने निकाले? शिंदे गुट ने मुंबई पुलिस से ठाकरे गुट के खिलाफ शिकायत की

मुंबईः मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गुट के खिलाफ जांच शुरू की है। शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) ने ईओडब्ल्यू में शिवसेना (ठाकरे गुट) के खिलाफ शिकायत की थी कि पिछले साल चुनाव आयोग की ओर से उन्हें ही असली शिवसेना घोषित किया गया था। बावजूद इसके पार्टी फंड से तकरीबन 50 करोड रुपए शिवसेना (ठाकरे गुट) ने निकाल लिए

। इस शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू यह पता कर रही है कि जिस बैंक अकाउंट से रकम निकाली गई, उस बैंक खाते को कौन ऑपरेट करता है? ईओडब्ल्यू ने आयकर विभाग को भी पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी मांगी है कि चुनाव आयोग का निर्णय आने के बाद से शिवसेना (शिंदे गुट) पार्टी का टैक्स कौन भर रहा है? समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने कुछ दिनों पहले मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसळकर से मुलाकात कर शिवसेना (ठाकरे गुट) के पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकायत दर्ज कराई थी।

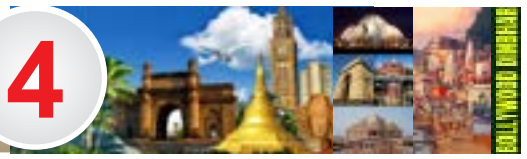

10 दिन, 150 करोड़ और 900 टेंडर्स!

मुंबई: अभी तक मनपा ब्रेफिक्र होकर बैठी हुई थी, वहीं अब उसने कुछ ही दिनों के भीतर १५० करोड़ के ९०० टेंडर्स जारी किए हैं, जिसमें प्रति टेंडर की औसत लागत १५ लाख से लेकर १८ लाख रुपए तक है। मनपा को भोले-भाले नागरिकों को उल्लू बनाना बखूबी आता है। मनपा चुनाव के दिन नजदीक आते ही जाग उठी है। मनपा ने कई अलग-अलग वॉर्डों में अलग-अलग कामों के लिए करीब १५० करोड़ रुपए की औसत लागत पर ९४० निविदाएं आमंत्रित की हैं, जिसमें २९२ टेंडर केवल दस दिनों के भीतर ही जारी किए गए।

मीरा भायंदर में लगी भीषण आग... 1 की मौत- कई झुग्गियां जलकर खाक

मुंबई : मीरा भायंदर में बुधवार (28 फरवरी) को भीषण आग लगने से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई. जानकारी के मुताबिक मुंबई के मीरा भायंदर के आजाद नगर में आग लगने की घटना सामने आई. आग की घटना में 1 शख्स की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि आजाद नगर में झोपड़पट्टी के इलाके में आग लगी जिसके बाद कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं. मीरा रोड शहर में धुआं के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखे.

दमकल विभाग की करीब सात गाड़ियों की मदद से आग पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश की जा रही है. आग बुझाने के दौरान अग्निशमन विभाग के 4 कर्मचारी भी जख्मी हुए हैं. पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.

मुंबई में भीषण आग में 1 की मौत

जानकारी के मुताबिक आग लगने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई. सिलेंडर ब्लास्ट में वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था. मृतक की पहचान दीपक उर्फ.पप्पू चौरसिया (पानवाला) के रूप में हुई है. तीन स्थानीय लोग मामूली रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग में कोई और जला तो नहीं है इसलिए फायर ब्रिगेड की टीम और सर्च भी कर रही है.

कई गोदाम और झुग्गियां राख में तब्दील

मुंबई के नजदीक भायंदर पूर्व में गोल्ड नेस्ट सर्कल के पास आजाद नगर झुग्गी बस्ती में बुधवार (28 फरवरी) सुबह करीब पांच बजे अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाना शुरू कर दिया लेकिन अभी भी पूरी तरह आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. जानकारी के मुताबिक आजाद नगर में गैराज, प्लास्टिक, स्क्रैप आदि हैं. 50 से अधिक झोपड़ी और गोदाम जलकर राख हो गई. आग बुझाने के दौरान 4 अग्निशमन के जवान मामूली घायल हुए है, जबकि एक स्थानीय नागरिक के भागने के दौरान गिरने से हाथ फ्रैक्चर होने की खबर है.

सेशन कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को मुंबई सुनाई फांसी की सजा

नवजात बच्ची के यौन शोषण के मामले में ठहराया दोषी

मुंबई: मुंबई सेशन कोर्ट ने मंगलवार को तीन महीने की बच्ची के यौन शोषण के आरोप में दोषी पाए गए ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई है। संभवतः यह पहला मौका है जब कोर्ट ने किसी ट्रांसजेंडर को सजाएं मौत दी है,जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। अडिशनल सेशन जज एयू कदम ने यह फैसला सुनाया है। जज कदम ने ट्रांसजेंडर को नवजात बच्ची के रेप,हत्या और अपहरण के साथ पाक्सों के आरोपी में दोषी ठहराते हुए कहा कि दोषी शख्स को तब तक फांसी पर लटका कर रखा जाए। जब तक की उसकी मौत न हो जाए।

ट्रांसजेंडर को दी अपील के अधिकार की जानकारी

फैसले के बाद न्यायाधीश ने ट्रांसजेंड को उसके हाई कोर्ट में अपील करने के अधिकार के बारे में जानकारी दी। वैसे भी फांसी की सजा हाई कोर्ट के फैसले के अधीन होती है। इसलिए राज्य सरकार ट्रांसजेंडर की फांसी की सजा पर मुहर लगाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेगी। सरकारी वकील राकेश तिवारी ने बताया कि आरोपी की इस मामले में संलिप्तता को दशार्नेवाले कोर्ट में ठोस कई सबूत पेश किए गए थे। केस के कई परिस्थिति जन्य ऐसे साक्ष्य थे, जो आरोपी की भूमिका को उजागर करते थे। ट्रांसजेंडर को बच्ची को ले जाते हुए एक गवाह ने उसे आखरी बार देखा था, जिससे यह साफ हुआ कि आरोपी ने नवजात बच्ची का अपहरण किया। फि निर्मम तरीके से बच्ची की हत्या की। उन्होंने बताया कि मामले से बरी आरोपी के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी।

'पैसे न देने पर किया बेटी का अपहरण'

कफ परेड पुलिस ने 24 वर्षीय आरोपी ट्रांसजेंडर कन्हैया उर्फ कन्नू दत्ता चौगुले के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 8 जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर को शिकायतकर्ता के घर में बेटी के जन्म की जानकारी मिली थी। ट्रांसजेंडर पैसे की मांग को लेकर झोपड़पट्टी इलाके में शिकायतकर्ता के घर गया था। चूंकि शिकायतकर्ता की माली हालत ठीक नहीं थी। इसलिए उसने ट्रांसजेंडर को पैसे देने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज ट्रांसजेंडर ने शिकायतकर्ता की नवाजात बेटी का नौ जुलाई 2021 को अपहरण किया। फिर कफ परेड इलाके में स्थित खाडी में ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और पानी में डूबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने ट्रांसजेंडर और उसके साथी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 376 (बी,डी),363 201,34 और पाक्सो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। गौरतलब है कि ट्रांजेडर गिरफ्तारी के बाद से जेल में है।

रश्मि शुक्ला को कार्यकाल में लगभग दो साल का सेवा विस्तार

मुंबई: रश्मि शुक्ला अब 3 जनवरी, 2026 तक महाराष्ट्र की डीजीपी होंगी। पहले वह चार महीने बाद 30 जून को रिटायरमेंट होने वाली थीं। महाराष्ट्र गृह विभाग की तरफ से मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश निकाला गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है, जिसमें कई अन्य महत्वपूर्ण पदों के साथ डीजीपी की पोस्ट पर लाए गए व्यक्ति का कार्यकाल भी न्यूनतम दो साल फिक्स किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कई साल पहले निकाला था। कई अन्य राज्यों में अपने यहां दो साल के लिए डीजीपी का फिक्स कार्यकाल रखा भी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश को अमल में लाया है।

एक आईपीएस अधिकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश और महाराष्ट्र सरकार के मंगलवार के ऑर्डर के बीच एक पेच है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहता है कि जिस किसी को दो साल का फिक्स कार्यकाल दिया जाए, उसका उम्र के हिसाब से उस पद से रिटायर होने से पहले कम से कम छह महीने का कार्यकाल बाकी हो। रश्मि शुक्ला को डीजीपी बनाने का ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार ने 4 जनवरी, 2024 को निकाला था (उन्होंने 9 जनवरी को कार्यभार संभाला), उनका 30 जून को पहले रिटायरमेंट ड्यू था, इसलिए बतौर डीजीपी उनका 4 जनवरी से 30 जून, 2024 तक छह महीने का कार्यकाल पूरा नहीं हो रहा। इसमें 4 दिन का अंतर है। इस अधिकारी के अनुसार, संभव है कोई इस टैक्निकल कारण को आधार बनाकर इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। एक अन्य अधिकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने भी इस आदेश को निकालने से पहले कानूनी सलाह जरूर ली होगी।

24 साल की उम्र में बनीं आईपीएस

रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला है, जिन्हें डीजीपी बनाया गया। पिछली महाविकास अघाड़ी सरकार ने उन पर कई विपक्षी नेताओं के फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे और पुणे व मुंबई में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थीं। लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद इन सभी पुराने मामलों की फिर जांच हुई और उन्हें कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई। रश्मि शुक्ला साल, 1988 बैच की हैं। वह 24 साल की उम्र में आईपीएस बन गई थीं। रश्मि शुक्ला का यूपी के प्रयागराज से लंबा जुड़ाव रहा है। उन्होंने वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया।

छोटा राजन गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

मुंबई : मुंबई पुलिस ने वर्ली से छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक देसी पिस्तौल और कारतूस बरामद किये हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान श्याम तांबे उर्फ सेवियो रॉड्रिग्स (42) के रूप में हुई है, जिसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने कहा, 'मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को विशेष सूचना मिली थी कि तांबे मध्य मुंबई में वर्ली के जीजामाता नगर इलाके में आ रहा है। सूचना के अनुसार जाल बिछाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उसके पास से एक देसी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किये गये। उन्होंने कहा, 'वर्ली पुलिस थाने में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि तांबे छोटा राजन गिरोह का सक्रिय सदस्य था और उस पर मुंबई के विभिन्न पुलिस थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती, चोरी और शस्त्र अधिनियम सहित कई मामले दर्ज थे।

महाराष्ट्र विधान भवन में विपक्ष का प्रदर्शन, नेता नकली रिवाल्वर के साथ नजर आए...

मुंबई: महा विकास अघाड़ी के विधायकों ने राज्य में 'बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति' के लिए सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है. इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशन के दूसरे दिन विधान भवन के गेट पर विपक्ष के नेता नकली रिवाल्वर के साथ नजर आए. उन्होंने कहा, यह गुंडो की सरकार है. यहां पर गोलीबारी होती है. यहां बता दें, कुछ दिन पहले उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के अंदर शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के नेता महेश गायकवाड़ को बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने गोली मार दी थी. इसके बाद विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा था.

महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने नासिक, जलगांव, चंद्रपुर और वर्धा आदि सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का मुद्दा उठाया. जिसके कारण सोयाबीन, कपास, संतरा जैसी कई फसलों को नुकसान हुआ है. उनकी सरकार से मांग है कि फसल क्षति का निरीक्षण कराया जाये और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाये.

बीते दिनों भी विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वड्डेतिवार, कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट और अन्य विधायक विधान भवन की सीढ़ियों पर एकत्र हुए, बैनर प्रदर्शित किए और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाए. विपक्षी विधायकों ने राज्य सरकार पर कोटा के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी समुदायों को गुमराह करने का आरोप लगाया है. बता दें, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने अपना अनशन खत्म कर दिया है.

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८१ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com